Q.1) निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
1. जनांकिकीय निष्पादन
2. वन और पारिस्थितिकी
3. शासन सुधार
4. स्थिर सरकार
5. कर एवं राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवक्रमण के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया?
a) केवल दो
b) केवल तीन
c) केवल चार
d) सभी पाँच

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
विकल्प 1 सही है- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन से तात्पर्य जनसंख्या-संबंधी कारकों जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, जनसांख्यिकीय संरचना और समय के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन के आकलन से है। आयोग ने अपनी सिफारिशों के लिए 2011 के जनसंख्या डेटा का उपयोग किया। कम प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मानदंड पर उच्च अंक दिए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5% वेटेज देने का सुझाव दिया।
विकल्प 2 सही है- वन और पारिस्थितिकी पर्यावरणीय कारकों के आकलन को संदर्भित करता है, जिसमें वनों का संरक्षण, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन शामिल है। यह मानदंड सभी राज्यों में कुल घने जंगल के सापेक्ष प्रत्येक राज्य के भीतर घने जंगल के अनुपात की गणना करके निर्धारित किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वन और पारिस्थितिकी को 10% महत्व देने का सुझाव दिया।
विकल्प 3 गलत है- शासन सुधारों में सरकारी संचालन और सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय शामिल हैं। इस मानदंड को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा क्षैतिज कर हस्तांतरण के मानदंडों में से एक के रूप में नहीं माना गया था।
विकल्प 4 गलत है- स्थिर सरकार का तात्पर्य सरकारी संस्थानों की राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता से है। जबकि सरकार में स्थिरता एक वांछनीय कारक हो सकती है, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा क्षैतिज कर हस्तांतरण के मानदंड के रूप में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।
विकल्प 5 सही है- कर और राजकोषीय प्रयासों में कर संग्रह और राजकोषीय प्रबंधन में राज्य के प्रयासों का मूल्यांकन शामिल है। इस मानदंड का उपयोग कर संग्रह में बेहतर दक्षता वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह 2016-17 से 2018-19 तक तीन साल की अवधि में औसत प्रति व्यक्ति स्वयं कर राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से निर्धारित होता है। 15वें वित्त आयोग ने कर और राजकोषीय प्रयासों को 2.5% वेटेज देने का सुझाव दिया।
Source: UPSC CSE Pre 2023
Subject:) Economy
Subtopic:) Fiscal Policy

Q.2) आय के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करें :
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश
2. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर मिलने वाला ब्याज
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से आय
4. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन से लाभांश
5. राज्य सरकार को दिये गये ऋण की वसूली
6. सिक्कों के प्रचलन से लाभ

WWW.PDFNOTES.CO

उपरोक्त में से कितनी भारत सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ मानी जाती हैं?
a) केवल तीन
b) केवल चार
c) केवल पाँच
d) सभी छह

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
सरकारी बजट में **राजस्व प्राप्तियों को दो व्यापक श्रेणियों** में **वर्गीकृत किया जाता** है : **कर राजस्व** और **गैर-कर राजस्व। कर राजस्व में** सरकार द्वारा लगाए गए **करों और शुल्कों से प्राप्त सभी प्राप्तियाँ** शामिल होती हैं। **गैर-कर राजस्व में अन्य** सभी राजस्व प्राप्तियाँ शामिल होती हैं **जिन्हें सरकार अर्जित नहीं करती है** यह **करों का परिणाम है** लेकिन इसके निवेश, सेवाओं और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के माध्यम से।
विकल्प 1 सही है: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से लाभांश विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों में अपने निवेश से सरकार की कमाई का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
विकल्प 2 सही है: केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज गैर-कर राजस्व का दूसरा रूप है, क्योंकि यह सरकार की उधार गतिविधियों से कमाई का प्रतिनिधित्व करता है।
विकल्प 3 गलत है: जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो उत्पन्न राजस्व को पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। यह गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है।
विकल्प 4 सही है: भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन से लाभांश , जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों पर ब्याज और इसके घरेलू परिचालन से कमाई शामिल है, को गैर-कर राजस्व माना जाता है।
विकल्प 5 गलत है: जब सरकार पहले जारी किए गए ऋणों की वसूली करती है, तो इसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। यह गैर-कर राजस्व के रूप में योग्य नहीं है।
विकल्प 6 सही है: गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में नागरिकों से एकत्र किए गए करों के अलावा सरकार की आय भी शामिल होती है। सिक्कों की ढलाई से होने वाला मुनाफा सिक्के के अंकित मूल्य और उत्पादन लागत के बीच के अंतर से उत्पन्न होता है। इस अंतर से सरकार को आय होती है। आय या वस्तुओं पर करों के विपरीत, यह राजस्व धारा सीधे नागरिकों पर नहीं लगाई जाती है।
Source: Indian Economy by Ramesh Singh
https://www.indiabudget.gov.in/budget_archive/ub2005-06/rec/ntaxrev.pdf
https://www.moneycontrol.com/news/business/budget/budget-2024-what-is-non-tax-revenue-12007131.html#:~:text=from%20other%20sources.-,Non%2Dtax%20revenue%20refers%20to%20the%20income%20earned%20from%20sources,for%20the%20services%20it%20provides.
https://cag.gov.in/uploads/old_reports/union/union_compliance/2005_2006/Non_Tax_Receipts/Report_No_9/chap_1.pdf
Subject:) Economy
Subtopic:) Budgetary Economics

Q.3) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन " क्राउडिंग इन" शब्द के अर्थ को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है ?
a) सरकार द्वारा उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र वित्तीय बाजार में विस्थापित हो रहा है।
b) सरकार द्वारा बढ़ते खर्च के कारण वित्तीय बाजार में निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है।
c) सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार उधार ले रही है।
d) सरकार संकट में फंसी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए वित्तीय बचाव योजनाएँ प्रदान कर रही है।

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

विकल्प a ग़लत है। क्राउडिंग आउट उस घटना को संदर्भित करता है जहां सरकारी **उधारी बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है।**

विकल्प b सही है . " **क्राउडिंग इन**" उस घटना को संदर्भित करता है जहां **सरकारी खर्च या निवेश में वृद्धि अतिरिक्त निजी निवेश को आकर्षित करती है,** जिससे समग्र आर्थिक विकास और विस्तार होता है।

विकल्प c ग़लत है। सॉवरेन ऋण एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसे सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण और राष्ट्रीय ऋण के रूप में जाना जाता है। सरकारें सार्वजनिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उधार लेती हैं।

विकल्प d ग़लत है। बेलआउट पैकेज एक वित्तीय बचाव योजना है जो सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय संकट का सामना कर रही एक संघर्षरत कंपनी, उद्योग या अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाती है। इसमें आम तौर पर किसी संस्था को ढहने या अपने दायित्वों पर चूक करने से रोकने के लिए धन, ऋण, गारंटी या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना शामिल है। बेलआउट पैकेज अक्सर वित्तीय बाजारों को स्थिर करने, प्रणालीगत जोखिमों को रोकने, नौकरियों को संरक्षित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लागू किए जाते हैं।

ज्ञानकोष: **क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट के बीच अंतर**

जब सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति (उधार लेकर अधिक खर्च) अपनाती है तो दो संभावित प्रभाव होते हैं:

क्राउडिंग आउट - उधार लेकर वित्त पोषित उच्च सरकारी खर्च से निजी क्षेत्र की बचत में गिरावट आती है। यह दो मुख्य कारणों से है-

1) विस्तारवादी राजकोषीय नीति के साथ, निजी क्षेत्र के बचतकर्ता सरकारी बांड खरीदते हैं और इसलिए उनके पास निजी क्षेत्र के निवेश के लिए कम बचत होती है।
2) इसके अलावा, उच्च सरकारी उधारी से ब्याज दरें बढ़ती हैं और ये उच्च ब्याज दरें निवेश को कम करती हैं।

क्राउडिंग इन - इसका संबंध इस बात से है कि कैसे अधिक सरकारी खर्च कंपनियों को अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उच्च सरकारी व्यय के आय प्रभाव के कारण है। यदि अर्थव्यवस्था मंदी में है या पूरी क्षमता से नीचे है, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति आर्थिक विकास दर को बढ़ा सकती है और सकारात्मक गुणक प्रभाव पैदा कर सकती है, जिससे निजी क्षेत्र में अधिक निवेश होता है।

Source: https://www.economicshelp.org/blog/glossary/crowding-in-effect/

Subject:) Economy

Subtopic:) Fiscal Policy

Q.4) 'जीएसटी कंपोजीशन स्कीम' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोई व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 75 लाख से अधिक है, वह इस योजना का विकल्प नहीं चुन सकता है।
2. जीएसटी कंपोजीशन स्कीम के तहत कंपोजीशन लेवी का विकल्प चुनने वाले करदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
3. कंपोजीशन स्कीम के तहत करदाता विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को माल की आपूर्ति कर सकता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) तीनों

d) कोई नहीं

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

जीएसटी **कंपोजीशन स्कीम एक वैकल्पिक कर लगाने की विधि है जो रुपये तक के टर्नओवर** वाले छोटे करदाताओं के लिए है। **75 लाख (कुछ राज्यों के लिए 50 लाख रुपये)।** इसका उद्देश्य छोटे पैमाने के करदाताओं के लिए कराधान को सरल बनाना और अनुपालन लागत को कम करना है।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 1 सही है: निम्नलिखित व्यक्तियों को जीएसटी संरचना योजना का **विकल्प चुनने की अनुमति नहीं है :**
a) एक अनौपचारिक कर योग्य व्यक्ति या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति;
b) **आपूर्तिकर्ता जिनका कुल कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में 75 लाख रुपये (कुछ राज्यों के लिए 50 लाख रुपये) को पार कर गया।**
c) आपूर्तिकर्ता जिसने अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से कोई सामान या सेवाएँ खरीदी हैं, जब तक कि उसने रिवर्स चार्ज के आधार पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया हो;
d) रेस्तरां सेवा के अलावा अन्य सेवाओं का आपूर्तिकर्ता;
e) ऐसे सामान की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति जो जीएसटी कानून के तहत कर योग्य नहीं हैं;
f) माल की अंतर-राज्यीय बाहरी आपूर्ति करने वाले व्यक्ति;
g) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता, जिन्हें धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है
कथन 2 सही है: जीएसटी कंपोजीशन योजना के तहत कंपोजीशन लेवी का विकल्प चुनने वाले करदाता **अपनी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर सकते हैं** , जो सरलीकृत कर संरचना के लिए एक समझौता है।
कथन 3 गलत है: घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) तक आपूर्ति को **अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपोजीशन स्कीम के तहत नामांकित करदाताओं को माल की अंतर-राज्यीय बाहरी आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है।** इसलिए, एसईजेड इकाई को माल की आपूर्ति करने के लिए, एक व्यक्ति को नियमित करदाता के रूप में पंजीकृत होना होगा।
Source: https://cbic-gst.gov.in/pdf/faq-manual/faq-composition-levy-revised.pdf
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

Q.5) भारत की नवनिर्मित संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नए संसद भवन का लोकसभा कक्ष कमल के फूल जैसा दिखता है।
2. पूरी इमारत को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न 1 न 2

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण स्वदेशी तौर पर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था और इमारत का डिज़ाइन पद्म श्री वास्तुकार बिमल पटेल द्वारा तैयार किया गया था।
कथन 1 गलत है: लोकसभा कक्ष को मोर की समानता में डिजाइन किया गया है और राज्यसभा कक्ष कमल के समान है।
कथन 2 सही है: अपनी भव्यता से परे, नया संसद भवन पर्यावरणीय स्थिरता का एक प्रतीक है। अपने **प्लैटिनम-रेटेड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन और GRIHA 5-स्टार रेटिंग के साथ** , यह हरित भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है।
Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 5
Subject:) Current Affairs
Subtopic:) Parliament of India

WWW.PDFNOTES.CO

Q.6) पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केवल सरकारी कर्मचारी ही ओपीएस के तहत पात्र थे, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी एनपीएस के तहत शामिल हो सकते हैं।
2. ओपीएस के तहत, पेंशन पर कर का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि एनपीएस के तहत पेंशन का कुछ हिस्सा कर योग्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न 1 न 2

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत में दो पेंशन योजनाएं हैं।

कथन 1 सही है: ओपीएस के तहत, केवल सरकारी कर्मचारी ही पेंशन योजना के लिए पात्र थे, जबकि एनपीएस निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित भारत के 18-60 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए खुला है।

कथन 2 सही है: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत, पेंशन पर कोई कर नहीं है। हालाँकि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, एनपीएस कॉर्पस का 60% कर-मुक्त है जबकि शेष 40% कर योग्य है।

ज्ञानधार:

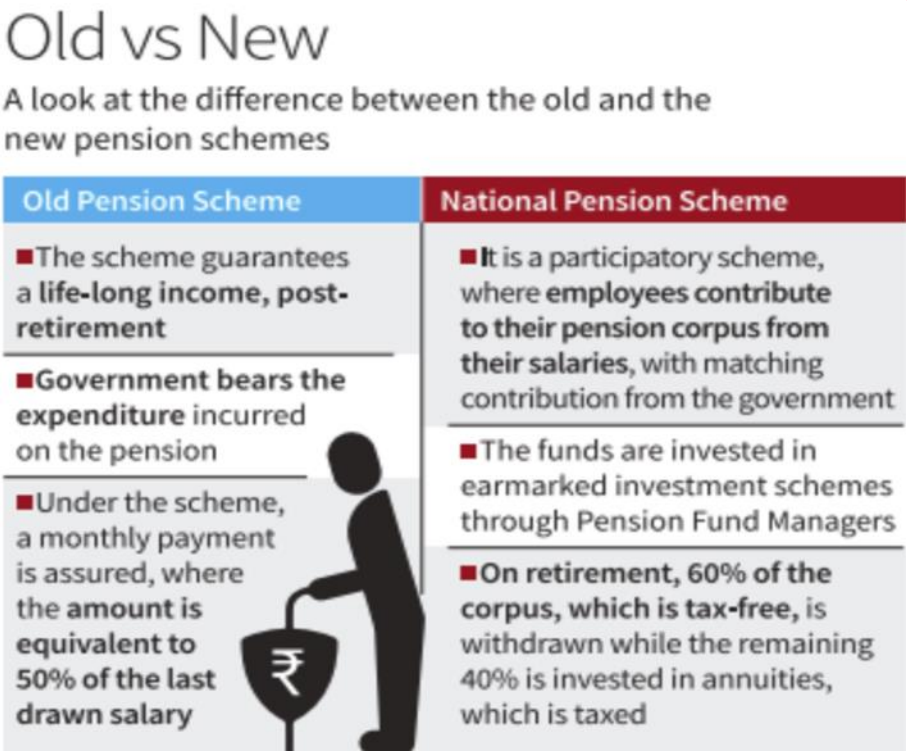

Source: https://economictimes.indiatimes.com/wealth/save/ops-vs-nps-demand-to-restore-ops-in-place-of-nps-for-central-government-employees-know-what-govt-says/articleshow/107264906.cms?from=mdr

Subject:) Economy

Subtopic:) Fiscal Policy

WWW.PDFNOTES.CO

Q.7) निम्नलिखित में से कौन सा कथन "राजकोषीय अपव्यय (Fiscal profligacy)" की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

a) एक ऐसा परिदृश्य जहां सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करों को कम करती है।
b) सरकार की अपने राजकोषीय दायित्वों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक उधार पर भारी निर्भरता है।
c) ऐसी स्थिति जहां सरकार अपनी क्षमता से अधिक खर्च करती है, जिससे ऋण और घाटे का स्तर अस्थिर हो जाता है।
d) सरकार के राजकोषीय उपायों का उद्देश्य किसी अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करना है।

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जून में जारी अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में, राजकोषीय अपव्यय के कारण राज्यों के बीच उच्च ऋण स्तर पर सावधानी बरती है।

राजकोषीय अपव्यय से तात्पर्य अपने साधनों से परे अत्यधिक सरकारी खर्च से है, जो अक्सर बजट घाटे, ऋण संचय और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। यह अल्पकालिक लाभ, बढ़ती मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है। सतत आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

हाल के दिनों में यह देखा जा सकता है कि सरकार ऋण के पैसे को लोकलुभावन उपहारों जैसे हस्तांतरण भुगतान, मुफ्त उपहार आदि पर खर्च कर रही है, जिससे कोई अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न नहीं होता है, जिसके **परिणामस्वरूप सरकार पर ऋण का बोझ बढ़ जाता है।** लंबे समय में स्थिति के परिणामस्वरूप आर्थिक अस्थिरता पैदा होगी।

Source: https://www.thehindu.com/opinion/lead/states-freebies-and-the-costs-of-fiscal-profligacy/article65573164.ece

Subject:) Economy

Subtopic:) Budgetary Economics

Q.8) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ई-वे बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए अनिवार्य नहीं है।
2. ताजे फल और सब्जियों के परिवहन को ई-वे बिल प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है।
3. इसे माल की आवाजाही के लिए केवल जीएसटी पंजीकृत ट्रांसपोर्टर द्वारा ही जेनरेट किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

ई-वे बिल एक दस्तावेज है जिसे पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ले जाना आवश्यक है, जैसा कि सरकार द्वारा वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में अनिवार्य रूप से इसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 138 के साथ पढ़ा जाता है।

कथन 1 ग़लत है: ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का संक्षिप्त रूप, जीएसटी प्रणाली के भीतर ऑनलाइन बनाने के लिए आवश्यक एक दस्तावेज है। विशिष्ट मूल्य से अधिक मूल्य वाले माल के परिवहन के लिए यह आवश्यक है, चाहे उनका परिवहन राज्यों के बीच किया जा रहा हो या एक ही राज्य के भीतर किया जा रहा हो। शिपिंग से पहले, ई-वे बिल तैयार किया जाना चाहिए और इसमें माल के बारे में व्यापक जानकारी होनी चाहिए, जिसमें प्रेषक, रिसीवर और ट्रांसपोर्टर के बारे में विवरण शामिल हों।

कथन 2 सही है: ताजे फल और सब्जियों सहित, लगभग 153 वस्तुओं को इसके परिवहन के लिए ई-वे बिल प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 3 गलत है: यह **पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों** द्वारा ई-वे बिल प्रणाली के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल से उत्पन्न होता है जो इस तरह की आवाजाही शुरू होने से पहले माल की खेप की आवाजाही का कारण बनता है। अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर सामान्य पोर्टल पर नामांकन कर सकता है और अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल तैयार कर सकता है।

Source:
https://docs.ewaybillgst.gov.in/html/faq.html#:~:text=e%2Dway%20bill%20is%20a,of%20the%20rules%20framed%20thereunder.
https://www.thehindubusinessline.com/economy/common-use-items-exempt-from-eway-bill-under-gst/article9818425.ece
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

Q.9) प्रतिभूति लेनदेन कर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है।
2. यह तभी लगाया जाता है जब निवेशक वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ कमाता है।
3. यह ऑफ-मार्केट प्रतिभूति लेनदेन पर लागू नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
भारतीय शेयर बाजार में स्टॉक, डेरिवेटिव और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से जुड़े लेनदेन पर सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) लगाया जाता है। 2004 में भारत में पेश किया गया, एसटीटी को सरकार द्वारा शेयर बाजार लेनदेन से राजस्व उत्पन्न करने और विनियमित करने में मदद करने के लिए एकत्र किया जाता है।
कथन 1 सही है: प्रतिभूति लेनदेन कर **प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों पर लगाया जाता है और इसकी गणना लेनदेन मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है।** एसटीटी की दर लेनदेन के प्रकार और शामिल प्रतिभूतियों की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है।
कथन 2 ग़लत है: प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) किसी भी लाभ या हानि की परवाह किए बिना **लेनदेन मूल्य पर लगाया जाता है और इसलिए स्टॉक में लाभदायक और हानि-रहित लेनदेन दोनों पर लागू होता है।**
कथन 3 सही है: एसटीटी शुल्क **केवल देश में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए शेयर लेनदेन पर लागू होता है। ऑफ-मार्केट शेयर लेनदेन एसटीटी के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।**
Source: https://www.livemint.com/market/stock-market-news/demat-account-what-are-the-tax-implications-of-transactions-securities-transaction-tax-ltcg-stcg-capital-gains-tax-11710237653578.html
https://www.bankbazaar.com/tax/securities-transaction-tax.html
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

WWW.PDFNOTES.CO

Q.10) कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित विभिन्न रिपोर्टों/सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

रिपोर्ट	द्वारा प्रकाशित
1. भारत न्याय रिपोर्ट	भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार का कार्यालय।
2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक	रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
3. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई)	ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी)।

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) तीनों

d) कोई नहीं

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

युग्म 1 ग़लत है: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट्स द्वारा शुरू की गई एक पहल है (सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा नहीं)। 2019 में, टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, DAKSH, TISS-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लाइव्स के साथ साझेदारी में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। रिपोर्ट **न्याय वितरण के "चार स्तंभों" के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के डेटा को संकलित और वर्गीकृत करती है: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता।**

युग्म 2 सही है: विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) द्वारा 2002 से प्रकाशित किया गया है। यह पत्रकारों के लिए उपलब्ध मीडिया स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। यह मीडिया स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है जो बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया पर्यावरण और स्व -सेंसरशिप, पारदर्शिता और कानूनी ढांचे और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है।

युग्म 3 गलत है: ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (जीटीआई) इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है, न कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा। सूचकांक आतंकवाद में प्रमुख वैश्विक रुझानों और पैटर्न का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। नवीनतम सूचकांक (2023) के अनुसार, भारत 13वें स्थान पर है और अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है।

Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 10

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) International Reports

Q.11) भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन-सा भारत सरकार की चिन्ता का प्रमुख कारण है?

a) स्थावर संपदा (real estate) के क्रय और विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन

b) अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय

c) राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास

d) कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

काले धन में अवैध गतिविधि के माध्यम से अर्जित सभी धन और अन्यथा कानूनी आय शामिल है जो कर उद्देश्यों के लिए दर्ज नहीं की जाती है। काला धन वित्तीय रिसाव का कारण बनता है, क्योंकि **बिना रिपोर्ट की गई आय, जिस पर कर नहीं**

WWW.PDFNOTES.CO

लगता है, सरकार को राजस्व हानि का कारण बनती है। इसके अलावा, ये फंड शायद ही कभी बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करते हैं। परिणामस्वरूप, वैध छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है।

Source: UPSC CSE Pre 2021

Subject:) Economy

Subtopic:) Fiscal Policy

Q.12) निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वित्त में "स्वर्णिम नियम" का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

a) सरकार का पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से अधिक होना चाहिए।

b) सरकार को केवल पूंजी निर्माण के वित्तपोषण के लिए उधार लेना चाहिए न कि वर्तमान खर्च के वित्तपोषण के लिए।

c) सरकारी कर्ज अपने देश की जीडीपी का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

d) सरकार को हर समय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

सार्वजनिक वित्त का स्वर्णिम नियम यह है कि **उधार ली गई राशि का उपयोग राजस्व व्यय के बजाय पूंजी निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। संक्षेप में, सरकार जो भी उधार लेती है, उसे उत्पादक निवेश के लिए उपयोग करना चाहिए।**

Source: https://www.deccanherald.com/opinion/adhering-to-the-golden-rule-of-public-finance-2-2891855

Subject:) Economy

Subtopic:) Public Finance in India

Q.13) भारत में कराधान प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यक्तिगत आयकर की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

a) प्रगतिशील कर (Progressive tax)

b) प्रतिगामी कर (Regressive tax)

c) आनुपातिक कर (Proportional tax)

d) अधोगामी कर (Digressive tax)

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

कर प्रणालियाँ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से **सरकारें नागरिकों** और **कॉर्पोरेट संस्थाओं पर शुल्क** लगाकर अपने व्यय का वित्तपोषण करती हैं। करों को मुख्य रूप से **तीन प्रकारों** में **वर्गीकृत किया गया है** : **प्रगतिशील** , **प्रतिगामी** और **आनुपातिक।**

विकल्प a सही है: एक **प्रगतिशील कर करदाता की भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत** के आधार पर **गरीबों की तुलना में अमीरों पर उच्च दर** लगाता है , जिससे यह विभिन्न आय समूहों में **समान हो जाता है।** यह प्रणाली **निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है** , क्योंकि यह उन लोगों पर **बड़ा वित्तीय बोझ डालती है जो ऐसा कर सकते हैं** वे अपनी आय के अनुपात में अधिक भुगतान करने में **सक्षम हैं।** ऐसे कर का उदाहरण भारत में आयकर है।

विकल्प b गलत है: एक **प्रतिगामी कर समान रूप से लागू किया जाता है** , जिसके परिणामस्वरूप **कम आय वाले लोगों** पर **अधिक बोझ पड़ता है।** भारत में व्यक्तिगत आयकर इस तरह से संचालित नहीं होता है, जहां कर प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाया गया है। ऐसे कर का उदाहरण भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) है।

विकल्प c गलत है: आनुपातिक **कर , जिसे फ्लैट टैक्स** के रूप में भी जाना जाता है , **सभी पर समान दर लागू करता है आय स्तर।** सरल होते हुए भी, यह नहीं है कि भारत की व्यक्तिगत आयकर प्रणाली कैसे काम करती है, क्योंकि भारत आय वर्ग के आधार पर एक स्तरीय कर दर प्रणाली लागू करता है। बिक्री कर को एक प्रकार का आनुपातिक कर माना जा सकता है क्योंकि सभी उपभोक्ताओं को, कमाई की परवाह किए बिना, समान निश्चित दर का भुगतान करना होगा।

WWW.PDFNOTES.CO

विकल्प d ग़लत है: अधोगामी कर एक प्रकार के कर को संदर्भित करता है जिसमें उच्च आय वाले लोग कम आय वाले लोगों की तुलना में अपनी आय के प्रतिशत के रूप में कम कर का भुगतान करते हैं। अधोगामी कर नीचे से ऊपर तक धन का पुनर्वितरण करते हैं।

Source: Indian Economy by Ramesh Singh

https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/financial-insights-and-beyond/examining-the-tax-structure-in-india-perspectives-comparisons-and-suggestions-55864/

https://www.livemint.com/money/personal-finance/where-does-india-stand-in-the-world-in-comparison-of-individual-tax-rates-11675002374282.html

https://timesofindia.indiatimes.com/business/budget/budget-2024-income-tax-progressive-taxation-and-redistribution-policy-recommendations/articleshow/107300095.cms

Subject:) Economy

Subtopic:) Taxation

Q.14) 'कटौती प्रस्ताव' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

यह बजट अधिनियमित करते समय अनुदान की मांग के लिए मतदान के दौरान लोकसभा में पेश किया गया एक प्रकार का संसदीय प्रस्ताव है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो बजटीय मांग 100 रुपये कम हो जाएगी। यह विशेष रूप से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली एक विशिष्ट शिकायत को दूर करने के लिए प्रस्तावित है।

उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार के कटौती प्रस्ताव का वर्णन करते हैं?

a) नीति कटौती प्रस्ताव
b) आर्थिक कटौती प्रस्ताव
c) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव
d) इनमे से कोई भी नहीं

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध करने के लिए लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है। कटौती प्रस्ताव तीन मुख्य प्रकार के होते हैं जैसे नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती।

विकल्प a ग़लत है: नीति में कटौती की मांग को अस्वीकार करने के लिए मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने की मांग की गई है, जो मांग को कम करने वाली नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है।

विकल्प b गलत है: आर्थिक **कटौती** प्रस्ताव एक विशिष्ट राशि के लिए मांग के आवंटन में कमी की मांग करता है। यह उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभावित हो सकती है। ऐसी निर्दिष्ट राशि या तो मांग में एकमुश्त कमी हो सकती है या मांग में किसी वस्तु की चूक या कमी हो सकती है।

विकल्प c सही है: एक सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है ताकि **मांग की राशि 100 रुपये कम हो जाए।** यह एक विशिष्ट शिकायत को दूर करने के लिए है जो भारत सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में है।

Source: https://www.business-standard.com/about/what-is-cut-motion

Subject:) Economy

Subtopic:) Budgetary Economics

Q.15) राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था।
2. इसका लक्ष्य 2026-27 के अंत तक बिजली में गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता की हिस्सेदारी को दो-तिहाई से अधिक तक बढ़ाना है।

WWW.PDFNOTES.CO

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022-27 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई थी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करने और पांच वर्षों में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022-27 (एनईपी) की परिकल्पना है कि गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता की हिस्सेदारी 2026-27 के अंत तक 57.4% तक बढ़ने की संभावना है और इसके आगे बढ़कर 68.4% होने की संभावना है। 2031-32 के अंत में अप्रैल'2023 तक लगभग 42.5%।
Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 20
Subject:) Current Affairs
Subtopic:) National Electricity Plan

Q.16) पूंजीगत लाभ कर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे पेटेंट और ट्रेडमार्क अधिकारों के हस्तांतरण से होने वाले मुनाफे पर लगाया जा सकता है।
2. भारत में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर आम तौर पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर से अधिक है।
3. यह विशेष रूप से भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त पूंजीगत लाभ पर लागू होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है
पूंजीगत लाभ शब्द किसी भी लाभ या वृद्धि को संदर्भित करता है जो 'पूंजीगत संपत्ति' की बिक्री या हस्तांतरण से प्राप्त होता है। बिक्री से प्राप्त लाभ 'आय' श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसलिए, प्राप्त आय पर कर का भुगतान करना होगा। भुगतान किए गए कर को पूंजीगत लाभ कर के रूप में जाना जाता है और पूंजीगत लाभ दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (STCG) और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG)।
कथन 1 सही है: पूंजीगत लाभ कुछ परिसंपत्तियों जैसे आभूषण, वाहन, पट्टे के अधिकार, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, भवन, गृह संपत्ति और भूमि की बिक्री या विनिमय से प्राप्त आय और मुनाफे पर लगाया जाता है।
कथन 2 गलत है: आमतौर पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट (STCG) लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट (LTCG) से अधिक होता है. हाल के अंतरिम बजट 2024 के अनुसार, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर को 10% पर संरेखित किया जा सकता है और सभी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों (जैसे सूचीबद्ध और असूचीबद्ध इक्विटी/वरीयता शेयर, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड और आरईआईटी/इनविट इकाइयों जैसे उपकरणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों, बांड, डिबेंचर) के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 15% पर संरेखित किया जा सकता है।
कथन 3 गलत है: पूंजीगत लाभ कर भारत में सभी निवासियों की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त लाभ पर लागू होता है।
Source:

WWW.PDFNOTES.CO

https://timesofindia.indiatimes.com/business/faqs/income-tax-faqs/what-is-capital-gains-tax/articleshow/93588264.cms
https://www.livemint.com/money/personal-finance/budget-2024-long-term-capital-gains-tax-and-the-holding-period-for-different-assets-shares-mutual-funds-gold-land-11704984631995.html
https://www.mea.gov.in/images/pdf/OIFCPublication2009GuidebookonTaxationforOI.pdf
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

Q.17) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पीएमएनआरएफ से धनराशि का वितरण प्रधान मंत्री के विवेक पर किया जाता है।
2. इसका ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाता है।
3. पीएमएनआरएफ में सभी योगदान आयकर से मुक्त नहीं हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) भारत में बाढ़, भूकंप, चक्रवात और अन्य आपदाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए स्थापित एक ट्रस्ट है। यह फंड गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे व्यक्तियों और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले लोगों को भी सहायता प्रदान करता है। पीएमएनआरएफ एक स्वैच्छिक योगदान कोष के रूप में कार्य करता है, जिसमें व्यक्तियों, संगठनों और कॉरपोरेट्स से दान आता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी.
कथन 1 सही है: प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से संवितरण प्रधान मंत्री के विवेक पर और प्रधान मंत्री द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
कथन 2 गलत है: पीएमएनआरएफ का ऑडिट सरकार के बाहर एक स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सार्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर हैं। इस प्रकार, इसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है।
कथन 3 गलत है: पीएमएनआरएफ में सभी योगदान धारा 80 (G) के तहत आयकर से मुक्त हैं।
Source: https://pmnrf.gov.in/en/faqs/pmnrf
https://www.business-standard.com/about/what-is-pm-national-relief-fund
Subject:) Economy
Subtopic:) Fiscal Policy

Q.18) आर्थिक विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'राजकोषीय बाधा (Fiscal drag)' की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
a) ऐसी स्थिति जहां पिछले ऋणों पर ब्याज साल दर साल बढ़ रहा है।
b) ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति या आय वृद्धि करदाताओं को उच्च कर ब्रैकेट में ले जाती है।
c) ऐसी स्थिति जहां कर वृद्धि और खर्च में कटौती का संयोजन स्वचालित रूप से होने वाला है।
d) ऐसी स्थिति जहां सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खर्च बढ़ाती है और रोजगार के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करती है।

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

राजकोषीय बाधा एक आर्थिक शब्द है जिसके तहत मुद्रास्फीति या आय वृद्धि करदाताओं को उच्च कर ब्रैकेट में ले जाती है। यह वास्तव में कर दरों में वृद्धि किए बिना सरकारी कर राजस्व को बढ़ाता है।

विकल्प बी सही है: राजकोषीय दबाव उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें मुद्रास्फीति या आय वृद्धि करदाताओं को उच्च कर ब्रैकेट में ले जाती है। जैसे-जैसे करदाताओं की आय बढ़ती है, वे उच्च आयकर ब्रैकेट में जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय पर औसत कर की दर अधिक हो जाएगी। इस घटना से बढ़ती आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ बढ़ सकता है, जिससे डिस्पोजेबल आय कम हो सकती है, जिससे अपस्फीतिकारी नीतियां बन सकती हैं, या अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है।

राजकोषीय क्लिफ: शब्द "फिस्कल क्लिफ" उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां कर वृद्धि और खर्च में कटौती का संयोजन स्वचालित रूप से होने वाला है, आमतौर पर एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में। यह परिदृश्य तब उत्पन्न होता है जब कुछ कानूनों या नीतियों की समाप्ति तिथियां या ट्रिगर होते हैं, जिन्हें यदि संबोधित नहीं किया गया या बदला नहीं गया, तो राजकोषीय नीति में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बजटीय मामलों पर बहस के दौरान इस अवधारणा को प्रमुखता मिली, विशेष रूप से कर कटौती की समाप्ति और स्वचालित व्यय कटौती के कार्यान्वयन से संबंधित। राजकोषीय संकट के साथ चिंता यह है कि अचानक कर वृद्धि और खर्च में कटौती से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से मंदी या आर्थिक मंदी आ सकती है।

ज्ञानधार:

Source: https://www.investopedia.com/terms/f/fiscal-drag.asp

https://www.investopedia.com/terms/f/fiscalcliff.asp

Subject:) Economy

Subtopic:) Fiscal Policy

Q.19) भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: जीएसटी मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण पर लागू नहीं होता है, बल्कि केवल अंतिम उत्पाद पर लागू होता है।

कथन II: जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II कथन I के लिए सही स्पष्टीकरण है।

b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II कथन I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

d) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को, केंद्रीय और राज्य करों के एक जटिल संरचना की जगह, जीएसटी कानून लागू किए गए थे।

कथन I ग़लत है। जीएसटी केवल आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण **में जोड़े गए शुद्ध मूल्य पर लागू होता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट के निर्बाध** प्रवाह की अनुमति मिलती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है।

कथन II सही है। जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है क्योंकि यह निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। जीएसटी उस राज्य में लगाया जाता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है, जो उन वस्तुओं और सेवाओं का गंतव्य भी है। इसलिए इसे गंतव्य-आधारित कर कहा जाता है।

Source: https://gstcouncil.gov.in/brief-history-gst#:~:text=Destination%2Dbased%20Tax%3A%20GST%20is,burden%20on%20the%20end%20consumer. Subject:) Economy Subtopic:) Taxation

WWW.PDFNOTES.CO

Q.20) भारत की विदेश व्यापार नीति, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे विदेश व्यापार अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया था।
2. इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को माल व्यापार अधिशेष देश में बदलना है।
3. इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
भारत ने पिछली FTP (2015-2020) की जगह लेते हुए 2023 में अपनी नवीनतम विदेश व्यापार नीति (FTP) पेश की, जिसे 2020 में इसकी समाप्ति के बाद COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण बढ़ा दिया गया था। नई नीति 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई।
कथन 1 सही है: नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023, को विदेश व्यापार अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत अधिसूचित किया गया था।
कथन 2 गलत है: नई विदेश व्यापार नीति (FTP), 2023 का लक्ष्य 2030 तक भारत को माल व्यापार अधिशेष देश में बदलना नहीं है। इसके बजाय, यह भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, 2030 तक यूएस $ 2 ट्रिलियन के संयुक्त निर्यात आंकड़े को लक्षित करता है।
कथन 3 सही है: नए FTP 2023 का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी बनाना और जिलों को निर्यात हब (DEH) पहल के रूप में आगे बढ़ाना है। यह पहल जिला स्तर पर निर्यात को प्रोत्साहित करने और स्थानीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए बनाई गई है।
Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 19
https://www.isas.nus.edu.sg/papers/indias-foreign-trade-policy-2023-new-ideas-and-old-challenges/
Subject:) Current Affairs
Subtopic:) Foreign Trade Policy

Q.21) बजट के साथ, वित्त मंत्री संसद के समक्ष अन्य दस्तावेज़ भी रखते हैं जिनमें 'द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट' शामिल है। उपरोक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह अनिवार्य है
a) लंबे समय से चली आ रही संसदीय परंपरा
b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110(1) के कारण।
c) भारत के संविधान का अनुच्छेद 113 के कारण
d) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है
हर साल, केंद्रीय बजट प्रस्तुति के समय संसद के समक्ष एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(5) के तहत है।
Source: UPSC CSE Pre 2020
Subject:) Economy
Subtopic:) Budgetary Economics

WWW.PDFNOTES.CO

Q.22) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

पद	**अर्थ**
1. कर व्यय (Tax expenditure)	कर दर में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया।
2.कर लोच (Tax Elasticity)	सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया।
3.कर आधिक्य (Tax Buoyancy)	कर कानूनों के तहत प्रदान की गई विभिन्न छूटों के कारण सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a) केवल एक

b) केवल दो

c) तीनों

d) कोई नहीं

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

युग्म 1 गलत तरीके से मेल खाती है: कर व्यय कर कानूनों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न कटौतियों, छूटों, क्रेडिट और तरजीही दरों को संदर्भित करता है जो कुछ करदाताओं के लिए कर देयता में कमी का कारण बनता है। इन्हें सरकारी खर्च माना जाता है क्योंकि इनके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती है जो अन्यथा एकत्र किया जाता।

युग्म 2 गलत तरीके से मेल खाती है: कर लोच इस बात का माप है कि कर दर में बदलाव के प्रति कर राजस्व कितना संवेदनशील है। यह इंगित करता है कि जब सरकार कर दरों में बदलाव करेगी तो कर राजस्व में कितना बदलाव आएगा।

युग्म 3 गलत तरीके से मेल खाती है: कर आधिक्य मापता है कि कर राजस्व वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। एक आधिक्य कर प्रणाली में कर दर में वृद्धि के बिना, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ कर राजस्व में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि देखी जाती है, जो एक मजबूत और उत्तरदायी कर प्रणाली को दर्शाता है।

Source: https://taxfoundation.org/taxedu/glossary/tax-expenditure/,https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/17643e1a_542c_47c8_a833_91a90d156ac7/chapter3.pdf

Subject:) Economy

Subtopic:) Taxation

Q.23) भारत सरकार के बजट को मोटे तौर पर राजस्व और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1.राजमार्गों का निर्माण

2. सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन

3.सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन

4.खाद्य सब्सिडी

5.अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश

उपरोक्त में से कितने बजट के

a) केवल दो

b) केवल तीन

c) केवल चार

d) सभी पाँच

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

पूंजीगत व्यय किसी संगठन द्वारा संपत्ति, मशीनरी या बुनियादी ढांचे जैसी संपत्तियों में दीर्घकालिक निवेश के लिए आवंटित धन का प्रतिनिधित्व करता है। परिचालन खर्चों के विपरीत, जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, क्षमता का विस्तार करना या दक्षता में सुधार करना है, जिससे भविष्य में वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके।

विकल्प 1 सही है: राजमार्गों का निर्माण एक पूंजीगत व्यय है क्योंकि इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है जो कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेगा।

विकल्प 2 गलत है: सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन पूंजीगत व्यय नहीं है; यह एक राजस्व व्यय है जिसका उपयोग दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किया जाता है।

विकल्प 3 गलत है: सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक राजस्व व्यय है न कि पूंजीगत व्यय क्योंकि इससे संपत्ति का निर्माण नहीं होता है।

विकल्प 4 गलत है: राजकोषीय विवरण के अनुसार सब्सिडी राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें भोजन, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी शामिल हैं। 3.75 लाख करोड़ रुपये की प्रमुख सब्सिडी (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) राजस्व व्यय का 10.7% है।

विकल्प 5 सही है: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश को पूंजीगत व्यय माना जा सकता है यदि यह अचल संपत्तियों के अधिग्रहण या मौजूदा संपत्तियों के महत्वपूर्ण उन्नयन के लिए है।

Source:
https://www.investopedia.com/terms/c/capitalexpenditure.asp#:~:text=Capital%20expenditures%20are%20payments%20made,and%20other%20assets%20for%20growth.
https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2017/Chapter_1_-_Introduction_of_Report_No.24_of_2017_-_Compliance_audit_Union_Government_Air_Force_Reports_of_Defence_Services.pdf

Subject:) Economy

Subtopic:) Budgetary Economics

Q.24) निम्नलिखित पर विचार करें:

1. एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति
2. प्रति व्यक्ति आय कम होना
3. नकदी आधारित अर्थव्यवस्था की प्रधानता
4. उच्च स्तर की कर चोरी और बचाव

उपरोक्त में से कितने लोग भारत में कम कर-से-जीडीपी अनुपात में योगदान करते हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

कर-से-जीडीपी अनुपात किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के करों में एकत्र किए गए प्रतिशत को दर्शाता है, जो राजकोषीय स्वास्थ्य और सरकारी राजस्व सृजन **के प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य** करता है। यह आर्थिक गतिविधि के सापेक्ष कराधान की सीमा को दर्शाता है, जो सार्वजनिक वित्त, सामाजिक कार्यक्रमों और समग्र आर्थिक स्थिरता **को प्रभावित करता है, निवेश और विकास** की संभावनाओं को प्रभावित करता है।

विकल्प 1 सही है: भारत की अर्थव्यवस्था का एक **महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक रूप से संचालित होता है, जिसका अर्थ है कि कई लेनदेन और आय दर्ज नहीं की जाती** हैं और इस प्रकार कर नहीं लगाया जाता है।

WWW.PDFNOTES.CO

1) **अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार और आर्थिक गतिविधि** का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन **कर दायरे से** बाहर है।
विकल्प 2 सही है: एक बड़ी आबादी की आय कर योग्य सीमा से कम होने के कारण, संभावित कर राजस्व सीमित है।
1) भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जिसका मतलब है कि आबादी का एक छोटा हिस्सा कर-भुगतान वर्ग में आता है।
विकल्प 3 सही है: नकद लेनदेन को ट्रैक करना कठिन है, जिससे आय की कम रिपोर्टिंग होती है और कर संग्रह कम होता है।
1) भारत की अर्थव्यवस्था **नकदी पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे कर अधिकारियों** के लिए करों की प्रभावी ढंग से निगरानी करना और एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
विकल्प 4 सही है: कर चोरी **और परिहार प्रथाएं करों के प्रभावी संग्रह** को कम करती हैं। कर आधार को व्यापक बनाने के प्रयासों के बावजूद, कर अनुपालन में अभी भी महत्वपूर्ण अंतर हैं।
Source: https://m.economictimes.com/news/economy/policy/interim-budget-2024-what-is-tax-to-gdp-ratio-where-does-india-fare-on-this-indicator/articleshow/73222499.cms?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=en&cc=IN&safesearch=moderate
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

Q.25) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन-I: मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है।
कथन-II: मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान खींची गई थी।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और विवरण-II विवरण-I के लिए सही स्पष्टीकरण है।
b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और विवरण-II विवरण-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।
c) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
d) कथन I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

कथन-I गलत है: मैकमोहन रेखा भारत और चीन (पाकिस्तान नहीं) के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, ने मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया, जो भूटान से म्यांमार तक 890 किमी लंबी है।
कथन-II सही है: शिमला कन्वेंशन को आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन के रूप में वर्णित किया गया था, जिस पर **1914 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस कन्वेंशन ने एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 'मैकमोहन लाइन' को जन्म दिया। हालाँकि, चीन में 1949 में कम्युनिस्ट** पार्टी के सत्ता में आने के बाद से मैकमोहन लाइन पर विवाद है और वास्तव में चीन ने अरुणाहकल के निवासियों को 'स्टेपल्ड वीज़ा' जारी किया है और हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश में नौ स्थानों के लिए नए नामों की घोषणा की है।
Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 12
Subject:) Current Affairs
Subtopic:) McMahon Line

WWW.PDFNOTES.CO

Q.26) निम्नलिखित पर विचार करें:
1. भविष्य निधि
2. छोटी बचत
3. डाकघर जमा
4. प्रेषण (Remittances)
5. न्यायिक जमा (Judicial Deposits)
उपरोक्त में से कितनी राशि से प्राप्त आय भारत के सार्वजनिक खातों के अंतर्गत दर्ज की जाती है?
a) केवल दो
b) केवल तीन
c) केवल चार
d) सभी पाँच

Ans) d
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
भारत का सार्वजनिक खाता सरकारी लेखांकन का एक प्रमुख घटक है, जो समेकित निधि से अलग है। इसमें सार्वजनिक बचत, ऋण निधि और **अन्य देनदारियों सहित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा रखी गई धनराशि शामिल है। पारदर्शिता, जवाब**देही और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन फंडों को अलग से प्रबंधित किया जाता है। सार्वजनिक खाते के अंतर्गत पांच प्रमुख खाते हैं: **(i) लघु बचत, भविष्य निधि और अन्य खाते (ii) आरक्षित निधि (iii) जमा और अग्रिम (iv) संदेहास्पद और विविध और (v) प्रेषण।**
विकल्प 1 सही है: भविष्य निधि **वह निधि है जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करते हैं, जो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को वापस** कर दिया जाता है। वे सार्वजनिक खाते का हिस्सा हैं क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा विश्वास में रखा जाता है।
विकल्प 2 सही है: सार्वजनिक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी विभिन्न छोटी बचत योजनाओं से संग्रह, सार्वजनिक खाते में शामिल किया जाता है।
विकल्प 3 सही है: डाकघरों में रखे गए बचत खाते भी सार्वजनिक खाते का हिस्सा हैं, क्योंकि सरकार इन निधियों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है।
विकल्प 4 सही है: प्रेषण देश में या बाहर भेजा गया धन है जिसे सरकार द्वारा अस्थायी रूप से सार्वजनिक खाते में शामिल किया जाता है।
विकल्प 5 सही है: न्यायिक मामलों से संबंधित जमा, जिसे सरकार ट्रस्ट में रखती है, सार्वजनिक खाते का हिस्सा है।
Source: https://www.business-standard.com/about/what-is-public-account
Subject:) Economy
Subtopic:) Public Finance in India

Q.27) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन -I- आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईई) द्वारा तैयार किया गया है।
कथन -II - अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है
c) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन-I सही है: आर्थिक सर्वेक्षण **मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया** जाता है। यह एक दस्तावेज़ है जो पिछले बारह महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है।

कथन-II सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है।

विवरण-II विवरण-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है: सीईए द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना आर्थिक आंकड़ों और प्रवृत्तियों की प्रस्तुति से संबंधित एक अभ्यास है, जो **अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता से अलग है।**

सर्वेक्षण प्रकाशित करना संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। एक कार्यकारी निर्णय के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाने लगा।

Source: https://economictimes.indiatimes.com/opinion/et-commentary/view-the-economic-survey-2021-22-is-the-first-one-to-document-the-surveyshistory/articleshow/89256439.cms?from=mdr#:~:text=Publishing%20the%20Survey%20is%20not%20a%20constitutional%20requirement.%20It%20started%20to%20be%20published%20because%20of%20an%20executive%20decision%20and%20a%20precedent%20was%20set.

Subject:) Economy

Subtopic:) Budgetary Economics

Q.28) निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें:

1. बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार।
2. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा करता है।
3. देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के आंतरिक और बाह्य पहलुओं का प्रबंधन करता है।

उपर्युक्त कार्यों के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है?

a) आर्थिक मामलों का विभाग
b) व्यय विभाग
c) वित्तीय सेवा विभाग
d) राजस्व विभाग

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) भारत के **वार्षिक बजट की सावधानीपूर्वक योजना और निर्माण का नेतृत्व करता है, जो वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमि**कताओं और संसाधन आवंटन की रूपरेखा तैयार करता है।

1) **डीईए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को विनियमित और घोषित करता है,** जिससे नागरिकों के बीच बचत को बढ़ावा देते हुए वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित होती है।

2) डीईए स्थायी आर्थिक विकास, **मौद्रिक स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के** लिए **विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए, घरेलू** और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों की देखरेख करता है।

3) इसके अतिरिक्त, यह **आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने** के लिए **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय भागीदारों के** साथ बातचीत सहित भारत के बाहरी आर्थिक संबंधों का प्रबंधन करता है।

Source: https://dea.gov.in/divisionbranch/major-functions

Subject:) Economy

Subtopic:) Fiscal Policy

WWW.PDFNOTES.CO

Q.29) उपकर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. लगाए गए उपकर से प्राप्त आय भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी
2. इसकी आय का उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
3. यह भारत में केवल अप्रत्यक्ष करों पर लगाया जाता है।
4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 270 उपकर को करों के विभाज्य पूल के दायरे से बाहर करने की अनुमति देता है जिसे केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना होगा।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
कथन 1 सही है: उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा लगाया गया कर है, और एकत्र किए गए धन को शुरू में भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जमा किया जाता है।
कथन 2 सही है: उपकर का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें एकत्र किया गया था। उदाहरण- **स्वच्छ भारत उपकर आदि।**
कथन 3 गलत है: भारत में उपकर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जाता है। उपकर से प्राप्त राजस्व विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाता है और इसे अन्यत्र खर्च नहीं किया जा सकता है।
कथन 4 सही है: अनुच्छेद 270, स्पष्ट रूप से मान्यता देता है कि उपकरों का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है और करों के विभाज्य पूल से बाहर रखा जाता है, और **यह केंद्र के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में** आता है।
Source: https://www.deccanherald.com/business/union-budget/union-budget-2024-what-is-cess-2866296
https://fincomindia.nic.in/archive/writereaddata/html_en_files/fincom15/StudyReports/Cesses%20and%20Surcharges.pdf
https://sansad.in/getFile/annex/262/AS173.pdf?source=pqars
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

Q.30) एशियाई विकास बैंक (ADB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ADB का मुख्यालय बीजिंग में है।
2. भारत ADB के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
3. इसमें एशिया के बाहर से कोई सदस्य नहीं है।
4. चीन ADB का सबसे बड़ा शेयरधारक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

WWW.PDFNOTES.CO

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत के लिए अपनी 2023-27 देश साझेदारी रणनीति शुरू की है, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाने, जलवायु-लचीला विकास को बढ़ावा देने और **सामाजिक और आर्थिक समावेशन को** गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया गया है।

कथन 1 गलत है: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

दूसरी ओर, **एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी**) एक **बहुपक्षीय विकास बैंक है** जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।

कथन 2 सही है: **एडीबी की स्थापना 1966 में भारत सहित 31 संस्थापक सदस्यों के साथ की गई थी।** इसलिए भारत ADB के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

कथन 3 गलत है: वर्तमान में, **एडीबी में 67 सदस्य हैं - जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत से और 19 बाहर से** हैं। इसलिए यह कथन कि एडीबी में एशिया के बाहर से कोई सदस्य नहीं है, सत्य नहीं है।

कथन 4 ग़लत है: हालाँकि चीन एक प्रमुख शेयरधारक है, लेकिन यह सबसे बड़ा नहीं है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दो सबसे बड़े शेयरधारक हैं, **प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6% है, इसके बाद चीन (6.4%) और भारत (6.3%) का स्थान है।**

Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 14

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) Asian Development Bank

Q.31) साल दर साल लगातार घाटे का बजट बना हुआ है। घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है?

1. राजस्व व्यय में कमी करना
2. नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना
3. सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना
4. उद्योगों का विस्तार करना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1
d) 1, 2, 3 और 4

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है

बजट घाटा तब होता है जब खर्च आय से अधिक हो जाता है।

नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने से बजट और बढ़ेगा। बजटीय सहायता द्वारा उद्योगों का विस्तार करने से सरकार के कर राजस्व में अल्पावधि में कुछ भी नहीं बढ़ेगा और इस प्रकार बजट घाटा बढ़ जाएगा। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और राजस्व व्यय को कम करना भारत सरकार के राजकोषीय बोझ को कम करने के दो प्रत्यक्ष तरीके हैं।

Source: UPSC CSE Pre 2015

Subject:) Economy

Subtopic:) Budgetary Economics

WWW.PDFNOTES.CO

Q.32) भारत में एंजेल टैक्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके एंजेल निवेशकों से धन प्राप्त करने पर भुगतान किया जाने वाला कर है
2. आयकर अधिनियम, 1961 एंजेल टैक्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
3. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को एंजेल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

कथन 1 सही है: एंजेल टैक्स गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करने के माध्यम से एंजेल निवेशकों से धन प्राप्त करने पर चुकाया जाने वाला कर है। परिचालन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियां अपने ब्रांड वैल्यू का उपयोग फंडिंग प्राप्त करने और उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करने के लिए करती हैं। कंपनी की अतिरिक्त कमाई को अन्य स्रोतों से आय माना जाता है।

कथन 2 सही है: एंजेल टैक्स के लिए कानूनी समर्थन आयकर अधिनियम, 1961, विशेष रूप से धारा 56(2)(viib) से मिलता है, जिसे वित्त अधिनियम, 2012 में पेश किया गया था।

कथन 3 सही है: प्रारंभ में, एंजेल टैक्स प्रावधान केवल निवासी निवेशकों से प्राप्त निवेश पर लागू थे । स्टार्टअप्स की बार-बार अपील के बाद, भारत सरकार ने 2019 के केंद्रीय बजट में कुछ राहतें पेश कीं। इन प्रावधानों के तहत, **DPIIT, या उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत पंजीकृत स्टार्टअप को ऐसे कराधान से छूट दी जाएगी।**

Source: https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/angel-tax-start-ups-cbdt-8985309/

Subject:) Economy

Subtopic:) Taxation

Q.33) विभिन्न प्रकार के करों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

कर	**विवरण**
1. यथामूल्य कर (Ad-Valorem tax)	वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर कर
2. पिगौवियन कर (Pigouvian Tax)	बाजार लेनदेन पर कर जो नकारात्मक बाह्यता पैदा करता है
3. टोबिन टैक्स (Tobin Tax)	स्पॉट एक्सचेंज लेनदेन पर कर।

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

a) केवल एक
b) सिर्फ दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

Ans) c

Exp) विकल्प c सही उत्तर है।

WWW.PDFNOTES.CO

युग्म 1 सही है . यथामूल्य कर वह कर है जो **किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर लगाया जाता है** । यथामूल्य कर का एक उदाहरण लक्जरी कारों पर 28% जीएसटी लगाना है। यहां अगर कार की कीमत 10 लाख रुपये है तो जीएसटी की रकम 2.8 लाख रुपये होगी। एक अन्य प्रकार का कर विशिष्ट कर है; जहां मात्रा पर कर लगाया जाता है।

युग्म 2 सही है . पिगौवियन कर, जिसका नाम 1920 के ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर सी. पिगौ के नाम पर रखा गया है, एक बाजार **लेनदेन पर एक कर है जो एक नकारात्मक बाह्यता** या अतिरिक्त लागत पैदा करता है, जो सीधे लेनदेन में शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन टैक्स आदि।

युग्म 3 सही है . टोबिन टैक्स, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के नाम पर रखा गया है, **एक मुद्रा के दूसरे मुद्रा में सभी स्पॉट रूपांतरणों पर प्रस्तावित कर है** । यह पहली बार 1970 के दशक में सुझाया गया था, टोबिन टैक्स ने मुद्रा सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने और वैश्विक वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में प्रमुखता प्राप्त की।

ज्ञान का आधार: **उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए पाप कर लगाया जाता है जिन्हें समाज के लिए अवांछनीय या हानिकारक माना जाता है** । पाप कर अवांछनीय वस्तुओं को इतना महँगा बना देते हैं कि विवेकशील उपभोक्ता को यह आदत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसे - तम्बाकू, जुआ उद्यम, शराब, सिगरेट, आदि।

Source:
https://lms.indianeconomy.net/glossary/ad-valorem-tax/#:~:text=Ad%20valorem%20tax%20is%20a,ad%20valorem%20is%20at%20value.
https://taxfoundation.org/taxedu/glossary/pigouvian-tax/
https://www.business-standard.com/podcast/finance/what-is-sin-tax-what-are-they-imposed-on-122021400044_1.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1996/06/pdf/spahn.pdf
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

Q. 34) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह भारत में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रत्यक्ष करों को लगाने और एकत्र करने से संबंधित मामले की देखरेख करता है।
3. लागत मुद्रास्फीति सूचकांक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

AAns) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
विभाग के सर्वोच्च निकाय के रूप में केंद्रीय राजस्व बोर्ड को करों के प्रशासन का कार्य सौंपा गया था। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। प्रारंभ में, बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का प्रभारी था। इसके बाद, **1963 में बोर्ड को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड।**

कथन 1 ग़लत है: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड **एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसका गठन किया गया है केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत नहीं)** ।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 2 सही है : इसके कार्यों में नीतियां बनाना, प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रह करने से संबंधित मामलों से निपटना और पूरे आयकर विभाग के कामकाज की निगरानी करना शामिल है। CBDT सरकार की नीतियों के अनुरूप **प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में विधायी परिवर्तन और दरों और कराधान की संरचना में बदलाव का भी प्रस्ताव करता है ।**

कथन 3 सही है: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) सालाना लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) जारी करता है। मुद्रास्फीति-समायोजित लागत मूल्य की गणना करने का सूत्र है: बिक्री के वर्ष का CII / खरीद के वर्ष के लिए CII * वास्तविक लागत मूल्य।

Source: https://incometaxindia.gov.in/pages/about-us/central-board-of-direct-taxation.aspx
https://www.dor.gov.in/sites/default/files/main01.pdf
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

Q.35) भारतीय राजनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार करें:

1. नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)
2. बहुजन समाज पार्टी (BSP)
3. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC)
4. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)
5. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)
6. आम आदमी पार्टी (AAP)

वर्तमान में उपरोक्त में से कितनों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है?

a) केवल तीन
b) केवल चार
c) केवल पाँच
d) सभी छह

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

चुनाव आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें अनुदान देता है उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता। अन्य पार्टियाँ हैं पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में घोषित किया गया।

विकल्प 1,2 और 6 सही हैं: हाल ही में चुनाव आयोग ने **आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है।** वर्तमान में **भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI (M)), बहुजन समाज पार्टी (BSP), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और AAP** भारत में राष्ट्रीय पार्टियां हैं ।

विकल्प 3,4 और 5 गलत हैं: हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग ने **अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया।**

Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 6
Subject:) Current Affairs Subtopic:) National Party

WWW.PDFNOTES.CO

Q.36) 15 वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसने करों के केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी।
2. करों के क्षैतिज हस्तांतरण के तहत जनसंख्या को सबसे अधिक महत्व दी।
3. इसने पोषण और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षेत्र विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की।
4. इसने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित आधुनिकीकरण कोष के गठन की सिफारिश की।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) सिर्फ दो
c) केवल तीन
d) सभी चार

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
वित्त आयोग (FC) एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 280), जो संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में एनके सिंह की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि को कवर करेंगी
कथन 1 ग़लत है . 15 वें वित्त आयोग ने करों के विभाज्य पूल का कुल 41% हस्तांतरण की सिफारिश की है। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिशत से 1% कम है। करों के विभाज्य पूल की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की 14 **वें वित्त आयोग की सिफारिश थी ।**
कथन 2 ग़लत है: 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करते समय निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया: (i) आय असमानता के लिए 45%, (ii) 2011 में जनसंख्या के लिए 15%, (iii) क्षेत्र के लिए 15%, (iv) 10% वन और पारिस्थितिकी के लिए, (v) जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 12.5%, और (vi) कर प्रयास के लिए 2.5%। इसलिए, क्षैतिज हस्तांतरण के लिए **आय अन्तराल को सबसे अधिक महत्व दिया गया** , न कि जनसंख्या को।
कथन 3 सही है . आयोग ने 2020-21 में पोषण के लिए 7,375 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। अंतिम रिपोर्ट में जिन क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान प्रदान किया जाएगा उनमें शामिल हैं: (i)**पोषण**, (ii) स्वास्थ्य, (iii) **पूर्व-प्राथमिक शिक्षा** , (iv) न्यायपालिका, और (v) रेलवे।
कथन 4 सही है . 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर पूंजीगत व्यय के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता और बजट आवंटन के बीच के अंतर को पाटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित आधुनिकीकरण कोष के गठन की सिफारिश की। इस फंड की आय का उपयोग निम्न लिए किया जायेगा-
1. रक्षा सेवाओं हेतु पूंजी निवेश ।
2. सीएपीएफ के लिए पूंजी निवेश और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण।
3. सैनिकों और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कल्याण निधि का एक छोटा सा घटक।

Source: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1693868
Subject:) Economy
Subtopic:) Fiscal Policy

Q.37) भारत में विदेशी ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह भारत द्वारा केवल गैर-रुपये मूल्यवर्ग की मुद्रा में लिए गए उधार को संदर्भित करता है।
2. वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के विदेशी ऋण का प्रबंधन करता है।
3. भारत में संप्रभु संस्थाओं पर बकाया विदेशी ऋण गैर-संप्रभु संस्थाओं की तुलना में अधिक है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

WWW.PDFNOTES.CO

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

कथन 1 गलत है: विदेशी ऋण देश के वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी संस्थानों या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों सहित विदेशी उधारदाताओं से उधार लिए गए कुल ऋण का हिस्सा है । इसे किसी भी मुद्रा (विदेशी और घरेलू मुद्रा दोनों) में अंकित किया जा सकता है।

कथन 2 सही है: भारत में केंद्र सरकार का विदेशी ऋण वित्त मंत्रालय के **आर्थिक मामलों के विभाग में बाहरी ऋण प्रबंधन इकाई (EDMU) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।**

कथन 3 गलत है: यह सत्य है कि गैर-संप्रभु संस्थाओं द्वारा बकाया बाहरी ऋण सरकारी संस्थाओं की तुलना में अधिक है। सरकारी संगठनों द्वारा बकाया बाहरी ऋण जिसे संप्रभु बाहरी ऋण (SED) के रूप में भी जाना जाता है, की राशि 133.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि गैर-संप्रभु संस्थाओं द्वारा गैर-संप्रभु ऋण के रूप में जाना जाने वाला ऋण सितंबर 2023 के अंत में 502.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

Source:
https://dea.gov.in/sites/default/files/India%27s%20Quarterly%20External%20Debt%20Report%20for%20quarter%20ending%20September%202023_0.pdf

Subject:) Economy

Subtopic:) Public Finance in India

Q.38) अंतरिम बजट (2024-2025) के संदर्भ में, सरकार के लिए राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करें:

1. निगम कर
2. आयकर
3. वस्तु एवं सेवा कर
4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
5. सीमा शुल्क

कुल कर राजस्व में उनके योगदान के घटते क्रम में करों का सही क्रम क्या है ?

a) 2-1-3-4-5

b) 2-3-1-4-5

c) 3-2-1-5-4

d) 3-2-1-4-5

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

सरकार के कुल राजस्व में करों का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है;

विकल्प 2 - आयकर - 19%

विकल्प 3 - वस्तु एवं सेवा कर - 18%

विकल्प 1 - निगम कर - 17%

विकल्प 4 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क - 5%

विकल्प 5 - सीमा शुल्क - 4%

ज्ञानधार:

WWW.PDFNOTES.CO

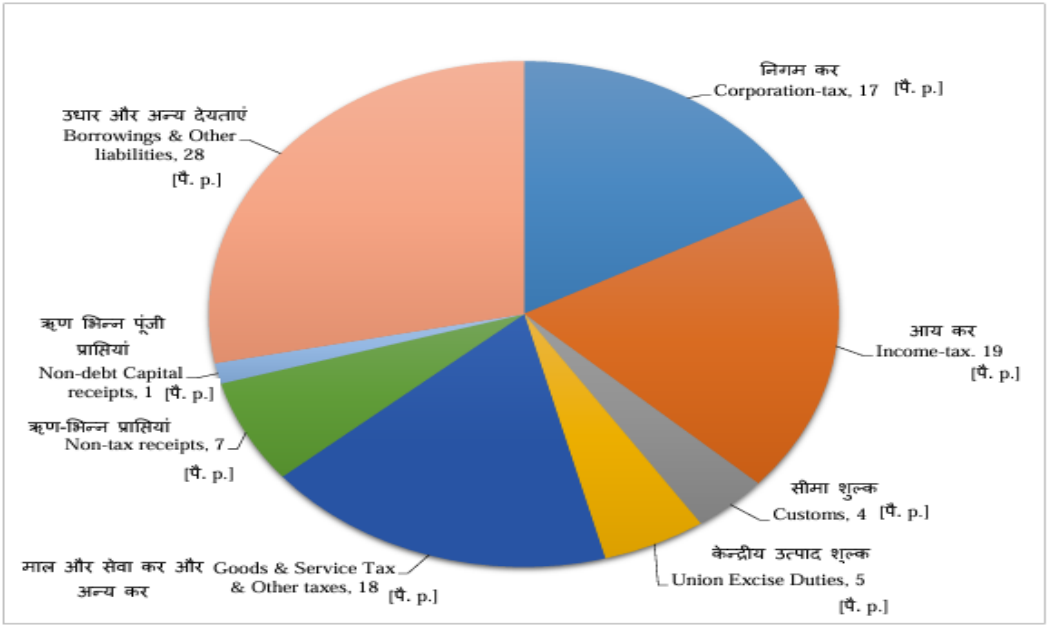

टिप्पणियां:- 1. कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में घटा दिया गया है।
2. आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

Notes :- 1. Total receipts are inclusive of States' share of taxes and duties which have been netted in the table on page 1.
2. Figures have been rounded off.

Source: https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag1.pdf
Subject:) Economy
Subtopic:) Budgetary Economics

Q.39) वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (FSDC) के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
2. यह एक वैधानिक निकाय है।
3. परिषद को अपनी गतिविधियाँ चलाने के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) सिर्फ दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है ।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की स्थापना वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करने और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
कथन 1 सही है . परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र नियामकों (आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए और एफएमसी) के प्रमुख वित्त सचिव और/या सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। यदि आवश्यक हो तो परिषद अपनी बैठक में विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है
कथन 2 ग़लत है . भारत सरकार की अधिसूचना के तहत दिनांक 30 दिसंबर 2010 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) का गठन किया गया है, इसलिए, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।

WWW.PDFNOTES.CO

कथन 3 सही है . परिषद वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के वृहद विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दों से निपटती है। **परिषद को अपनी गतिविधियाँ चलाने के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।**

Source: https://dea.gov.in/sites/default/files/StrucFSDC.pdf

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=95543

Subject:) Economy

Subtopic:) Fiscal Policy

Q.40) निम्नलिखित में से कौन से देश समूह अरब लीग के सदस्य हैं?

a) मिस्र, इराक, इज़राइल और सऊदी अरब

b) इंडोनेशिया, आर्मेनिया, मिस्र और सीरिया

c) वेनेजुएला, सोमालिया, इज़राइल और इथियोपिया

d) सीरिया, इराक, मिस्र और सोमालिया

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है

अरब लीग मध्य पूर्व और अफ्रीका में अरब राज्यों का एक अंतरसरकारी संगठन है। इसका गठन 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 1945 में किया गया था।

अरब लीग में वर्तमान में 22 सदस्य राज्य हैं, और वे अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीनी प्राधिकरण, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।

सीरिया, इराक, मिस्र और सोमालिया वर्तमान में अरब लीग के सदस्य हैं। हाल ही में, अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने दस साल से अधिक समय तक सदस्यता के निलंबन के बाद सीरिया की सदस्यता बहाल की। ब्राजील, इरिट्रिया, भारत, आर्मेनिया और वेनेजुएला लीग में पर्यवेक्षक देश हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल, इथियोपिया और इंडोनेशिया अरब लीग के **सदस्य नहीं हैं ।**

Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 12

Subject:) Current Affairs

Subtopic:) Arab League

Q.41) निम्नलिखित में से कौन सा कथन "राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal stimulus)" का उचित वर्णन करता है?

a) यह तेजी से आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा निवेश है।

b) यह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्रवाई है

c) यह अधिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों पर सरकार की गहन कार्रवाई है।

d) वित्तीय समावेशन की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार द्वारा एक अत्यधिक सकारात्मक कार्रवाई है

Ans) b

Exp) विकल्प b सही उत्तर है।

राजकोषीय प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था में कुल **मांग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई एक कार्रवाई है। यह कर कटौती या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के रूप में हो सकता** है। राजकोषीय प्रोत्साहन सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों को भी संदर्भित करता है जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए आम तौर पर करों या नियमों को कम करते हैं - या सरकारी खर्च बढ़ाते हैं।

Source: UPSC CSE Pre 2011

Subject:) Economy Subtopic:) Fiscal Policy

WWW.PDFNOTES.CO

Q.42) भारत की कराधान प्रणाली के ढांचे में, वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित वस्तुओं/वस्तुओं पर विचार करें:
1. टेबल सॉल्ट
2. मानव रक्त और उसके घटक
3. सीलबंद मिनरल वाटर
4. पहले से पैक और लेबल किया हुआ गुड़
5. खुला बिकने वाला दही
उपरोक्त में से कितने सामान/वस्तुओं को GST के तहत छूट प्राप्त है?
a) केवल दो
b) केवल तीन
c) केवल चार
d) सभी पाँच

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
भारत में 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (GST), **एक व्यापक, बहु-चरण, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। इसने करों के व्यापक प्रभा**व को खत्म करने और देश भर में कराधान में एकरूपता लाने के लिए वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि सहित कई पूर्ववर्ती करों को समाहित कर लिया है।
कथन 1 सही है: टेबल नमक को GST से छूट दी गई है, जो बुनियादी और आवश्यक वस्तुओं को कर के दायरे से बाहर रखने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सामान्य आबादी के लिए सस्ती रहें।
कथन 2 सही है: मानव रक्त और उसके घटकों की खरीद जीएसटी से मुक्त है।
कथन 3 गलत है: सीलबंद या पैक किया हुआ मिनरल वाटर GST के अधीन है क्योंकि इसे एक लक्जरी या गैर-आवश्यक वस्तु माना जाता है। **मिनरल वाटर पर जीएसटी लगाने का उद्देश्य उन वस्तुओं पर मानक दरों पर कर लगाना है जो बुनियादी आवश्यकताएं नहीं हैं।**
कथन 4 ग़लत है: केंद्र ने हाल ही में गन्ना गुड़ (गुड़), पा**ल्मिरा गुड़ (पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाले) सहित सभी प्रकार के गुड़ पर 2.5 प्रतिशत CGST और 2.5 प्रतिशत SGST लगाया है**, जबकि पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाले गुड़ के अलावा अन्य गुड़ पर शून्य GST लगता है।
कथन 5 सही है: हालिया अपडेट के अनुसार, GST व्यवस्था के तहत ताजा दूध और **पाश्चुरीकृत दूध पूरी तरह से छूट में रहेगा। इसी तरह, जब तक पनीर, दही और छाछ खुला बेचा जाता है,** यानी बिना किसी प्री-पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बेचा जाता है, तब तक कोई GST लागू नहीं होता है।
ज्ञानकोष:
1) कराधान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और उपभोक्ताओं पर कई कराधान के बोझ को कम करने के उद्देश्य से उपभोग के बिंदु पर वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू किया जाता है।
2) GST परिषद, जो भारत में GST से संबंधित सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, समय-समय पर GST से मुक्त वस्तुओं और सेवाओं की सूची की समीक्षा और संशोधन करती है।
3) ये निर्णय वस्तुओं और सेवाओं के सामाजिक-आर्थिक महत्व और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।
Source: http://www.msmedinewdelhi.gov.in/PDF2017-18/GST/List%20of%20Exempted%20Goods%20under%20GST%20with%20HSN%20Code.pdf
https://cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html
Subject:) Economy
Subtopic:) Taxation

WWW.PDFNOTES.CO

Q.43) भारत में अंतरिम बजट और लेखानुदान (Vote on Account) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संविधान में अंतरिम बजट का उल्लेख है, जबकि लेखानुदान का उल्लेख नहीं है।
2. अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियाँ दोनों शामिल होती हैं, जबकि लेखानुदान केवल व्यय से संबंधित होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Ans) b
Exp) विकल्प b सही उत्तर है।
कथन 1 गलत है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार, लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अल्पकालिक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान है, जो आम तौर पर नए वित्तीय वर्ष शुरू होने तक कुछ महीनों तक चलता है। जबकि अंतरिम बजट का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है.
कथन 2 सही है. हालाँकि दोनों **का उपयोग विनिमेय है, अंतरिम बजट वह होता है जिसमें** नई सरकार के कार्यभार संभालने और पूर्ण बजट प्रस्तुत करने तक की अवधि के **लिए राजस्व और व्यय दोनों विवरण शामिल होते** हैं, जबकि लेखानुदान में केवल सरकार के व्यय शामिल होते हैं।
Source:
https://www.thehindu.com/business/budget/how-is-interim-budget-different-from-annual-budget-what-can-be expected/article67776626.ece#:~:text=As%20there%20is%20no%20constitutional,the%20votes%20on%20account%20provision.
https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/industry/union-budget-2024-what-is-vote-on-account-and-how-is-it-different-from-interim-budget/107281306#:~:text=Though%20both%20are%20interchangeably%20used,includes%20only%20the%20government's%20expenditures.
Subject:) Economy
Subtopic:) Budgetary Economics

Q.44) राजकोषीय घाटे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा पिछले पांच वर्षों में लगातार घट रहा है।
2. 2024-25 अंतरिम बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 'बाह्य उधार' राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
राजकोषीय घाटा एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के कुल राजस्व और उसके कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। यह सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक ऋण की मात्रा को इंगित करता है। **राजकोषीय घाटा सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य और उसके बजट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता का एक**

WWW.PDFNOTES.CO

महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो उच्च राजकोषीय घाटा उधारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता में वृद्धि का कारण बन सकता है।
गणितीय रूप से, इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:
राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - कुल राजस्व (ऋण को छोड़कर)
कथन 1 गलत है: COVID-19 महामारी और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के राजकोषीय पैकेज के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में **राजकोषीय घाटा 9.5% हो गया**, जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 4.6 प्रतिशत था। 2020-21 से राजकोषीय घाटे में लगातार गिरावट आ रही है. वित्त वर्ष 2024-25 में इसके घटकर 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। इसलिए पिछले 5 वर्षों में इसमें लगातार गिरावट नहीं हो रही है।
कथन 2 गलत है: **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत बाजार उधार (सरकारी प्रतिभूतियाँ/G-Secs) है**, न कि बाहरी ऋण। केंद्रीय बजट 2023-24 में, 2023-24 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार ऋण का बजट ₹15,43,000 करोड़ रखा गया था।
Source: https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag2.pdf
https://www.livemint.com/economy/budget-2024-govt-pegs-fiscal-deficit-target-at-5-1-of-gdp-for-fy25-11706760732691.html#
Subject:) Economy
Subtopic:) Budgetary Economics

Q.45) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है।
2. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा संदर्भित अपराधों की जाँच कर सकता है।
3. हाल ही में भारत ICC का सदस्य बना।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।
कथन 1 गलत है: ICC न तो संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है और न ही संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। यह 1998 रोम क़ानून (Rome statute) द्वारा बनाया गया था और **1 जुलाई 2002 को लागू हुआ।**
कथन 2 सही है: ICC के पास सार्वभौमिक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अभाव है। यह केवल सदस्य राज्यों के भीतर या सदस्य राज्यों के नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों की जांच और मुकदमा चला सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित अपराधों की भी जाँच करता है। **ICC के निर्णय अपील के बिना अंतिम होते हैं और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं।**
कथन 3 गलत है: भारत ICC का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसने कभी भी 'रोम क़ानून' संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
Source: Forum IAS Quarterly Current Affairs APRIL 2023 – JUNE 2023-Page: 12
Subject:) Current Affairs
Subtopic:) International Criminal Court

WWW.PDFNOTES.CO

Q.46) यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो अंक 4, 5, 6, 7, 8 का उपयोग करके कितनी 5 अंकों वाली अभाज्य संख्याएँ बनाई जा सकती हैं?

a) 4
b) 2
c) 1
d) 0

Ans) d

Exp) विकल्प d सही उत्तर है।

प्रदत्त:
अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 4, 5, 6, 7 और 8 का उपयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या।
प्रयुक्त अवधारणा:
अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसे केवल स्वयं से ही विभाजित किया जा सकता है (उदाहरण - 2, 3, 5,7,11 आदि)
महत्वपूर्ण विभाज्यता नियम:-
2=अंतिम संख्या 2 का गुणज होनी चाहिए।
3= अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।
4 = अंतिम 2 अंक 4 के गुणज होने चाहिए
5 = अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए।
6= 2 और 3 की विभाज्यता नियम का पालन करना चाहिए।
गणना:
हम संख्या को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, इसलिए अंतिम अंक नियम के अनुसार, हम बाद में जांच सकते हैं।
3 की विभाज्यता से प्रारंभ करें
4+5+6+7+8=30
और 30, 3 से विभाज्य है
तो, संख्या का कोई भी संयोजन हमें 30 का योग देता है जो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी।
4, 5, 6, 7 और 8 का ऐसा कोई संयोजन नहीं है जो हमें एक अभाज्य संख्या दे।
Subject:) CSAT
Subtopic:) Quantitative Aptitude

Q.47) A और B 400 मीटर लंबे गोलाकार रास्ते पर 5 किमी की दौड़ लगाते हैं। उनकी गति का अनुपात 4:3 है। यदि वे एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं, तो पहले वाला दूसरे के पास से कितनी बार गुज़रेगा (शुरुआत को गुजरना/पार करना के रूप में नहीं गिना जाता है)?

a) 3
b) 4
c) 2
d) 5

Ans) a

Exp) विकल्प a सही उत्तर है।

जब तेज धावक अतिरिक्त 400 मीटर की दूरी तय कर लेगा तो वह धीमे धावक को पार कर जाएगा।
माना उनकी गति 4 मीटर/सेकंड और 3 मीटर/सेकंड है।
तो, उनकी सापेक्ष गति = 4 - 3 = 1 मीटर/सेकंड
तो, तेज़ धावक द्वारा धीमे धावक को पार करने में लिया गया समय = दूरी/सापेक्षिक गति = 400/1 = 400 सेकंड

WWW.PDFNOTES.CO

इसका मूल रूप से मतलब यह है कि तेज़ धावक हर 400 सेकंड या 6 मिनट 40 सेकंड में धीमे धावक को पार कर जाएगा।
अब, तेज दौड़ने वाले को पूरी दौड़ पूरी करने में लगा समय = कुल दूरी/गति = 5000/4 = 1250 सेकंड।
तो, तेज़ दौड़ने वाला पूरी दौड़ के दौरान धीमे दौड़ने वाले को तीन बार पार करेगा - 400 सेकंड, 800 सेकंड और 1200 सेकंड के बाद।
Subject:) CSAT
Subtopic:) Quantitative Aptitude

Q.48) निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें।
कथन 1: कोई भी एथलीट जो लंबी दूरी की दौड़ में माहिर नहीं है, वह पेशेवर पावरलिफ्टर भी नहीं है।
कथन 2: कुछ पेशेवर तैराकों ने ट्रायथलॉन में प्रतिस्पर्धा की है, जिसमें लंबी दूरी की दौड़ का खंड शामिल है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकाला जा सकता है?
a) सभी पेशेवर तैराक जिन्होंने ट्रायथलॉन में भाग लिया है, वे पेशेवर पावरलिफ्टर भी हैं।
b) ट्रायथलॉन में भाग लेने वाला कोई भी पेशेवर तैराक पेशेवर पावरलिफ्टर नहीं है।
c) कुछ पेशेवर तैराक जिन्होंने ट्रायथलॉन में प्रतिस्पर्धा की है, वे पेशेवर पावरलिफ्टर नहीं हैं।
d) उपरोक्त में से किसी का भी तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

Ans) c
Exp) विकल्प c सही उत्तर है।
आइए दिए गए कथनों का विश्लेषण करें:
कथन 1: "कोई भी एथलीट जो लंबी दूरी की दौड़ में माहिर नहीं है, वह पेशेवर पावरलिफ्टर भी नहीं है।" यह कथन स्थापित करता है कि लंबी दूरी की दौड़ में विशेषज्ञता रखने वाले एथलीटों और पेशेवर पावरलिफ्टरों के बीच कोई ओवरलैप नहीं है।
कथन 2: "कुछ पेशेवर तैराकों ने ट्रायथलॉन में प्रतिस्पर्धा की है, जिसमें लंबी दूरी की दौड़ का खंड भी शामिल है।" यह कथन इंगित करता है कि पेशेवर तैराकों का एक उपसमूह है जो ट्रायथलॉन प्रतियोगिताओं के भाग के रूप में लंबी दूरी की दौड़ में लगा हुआ है।
इन दोनों कथनों को मिलाकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ पेशेवर तैराक जिन्होंने ट्रायथलॉन में प्रतिस्पर्धा की है (और इसलिए लंबी दूरी की दौड़ में लगे हुए हैं) पेशेवर पावरलिफ्टर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लंबी दूरी के धावक और पेशेवर पावरलिफ्टर के बीच कोई ओवरलैप नहीं है। इसलिए, सही उत्तर C है। कुछ पेशेवर तैराक जिन्होंने ट्रायथलॉन में प्रतिस्पर्धा की है, वे पेशेवर पावरलिफ्टर नहीं हैं।
Subject:) CSAT
Subtopic:) Logical and Verbal Reasoning

निम्नलिखित 2 (दो) प्रश्नों के लिए दिशानिर्देश:
निम्नलिखित दो परिच्छेदों को पढ़ें और उन परिच्छेदों के बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों पर आपके उत्तर केवल परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए।

परिच्छेद-I

महान पुरातत्ववेत्ता अक्सर आपस में ही युद्धरत रहते हैं। उनका लक्ष्य भूकंपीय परिवर्तनों - सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय, यहां तक कि आनुवंशिक - की व्याख्या करना है। लेकिन वे ऐसा (शाब्दिक और आलंकारिक रूप से) भौतिक साक्ष्यों को छांटकर करते हैं जो बहुत कम और (शाब्दिक और आलंकारिक रूप से) खंडित होते हैं। इन तरीकों का मतलब है कि उनके लगभग सभी प्रकाशन अकादमिक मानकों के हिसाब से भी संकीर्ण और अत्यधिक शुष्क हैं। और यहां तक कि उन दुर्लभ अवसरों पर भी जब वे जर्नल लेख या मोनोग्राफ से परे उद्यम करते हैं, उनका लेखन शायद ही कभी सबसे पुरातात्विक रूप से सामान्य पाठक को भी लुभाता है। उदाहरण के लिए, हालांकि मेसोपोटामिया के महान पुरातत्वविदों ने शहरी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों की समझ में क्रांति ला दी है, लेकिन उनके बड़े आकार के मकबरे, जलधाराओं और निपटान पैटर्न के विस्तृत मानचित्रों और मिट्टी के बर्तनों के प्रकारों के सूक्ष्म चार्ट के साथ, इतिहास

WWW.PDFNOTES.CO

के कार्यों के बजाय क्षेत्रीय रिपोर्टों से मिलते जुलते हैं। लेकिन क्योंकि पुरातत्व सबसे बुनियादी प्रश्नों को संबोधित करता है और एक बेहद अधूरे रिकॉर्ड के माध्यम से मानव इतिहास में सबसे गहन परिवर्तनों की पड़ताल करता है - और शायद इसलिए कि यह लंबे समय तक अभिजात वर्ग और डाकूओं का प्रांत था -
इसने ऐसी निर्भीक व्याख्याओं को आमंत्रित किया है जिसमें अटकलें आसानी से सबूतों से परे हो सकती हैं। जब पुरातत्व सही ढंग से किया जाता है, तो यह अक्सर नीरस होता है; जब यह आकर्षक होता है, तो यह अक्सर गलत होता है।

Q.49) निम्नलिखित सभी कथन, यदि सत्य हैं, पुरातात्विक अनुसंधान की प्रकृति और इसके निहितार्थ के बारे में प्रस्ताव को कमजोर कर देंगे, सिवाय इसके:
a) आधुनिक प्रौद्योगिकियों के आगमन ने पुरातत्वविदों को अकादमिक कठोरता का त्याग किए बिना व्यापक और आकर्षक आख्यान तैयार करने में सक्षम बनाया है।
b) ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पुरातत्व में साहसिक, काल्पनिक व्याख्याएं निर्णायक रूप से सही साबित हुई हैं, जिससे अनुशासन की अपील बढ़ गई है।
c) पुरातात्विक प्रकाशनों का सूक्ष्म विवरण और संकीर्ण फोकस इस अनुशासन में अंतर्निहित नहीं है, बल्कि वर्तमान शैक्षणिक प्रकाशन वातावरण का परिणाम है।
d) अधूरे रिकॉर्ड के साथ काम करने की चुनौतियों के बावजूद, अनुशासन की कठोर कार्यप्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि इसके सबसे आकर्षक निष्कर्ष भी साक्ष्य में मजबूती से निहित हों।

Ans) d
Exp) विकल्प d सही उत्तर है।
विकल्प d सही उत्तर है क्योंकि यह दिए गए परिच्छेद के सार के साथ संरेखित है, जो कठोर, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और व्यापक, काल्पनिक कथाओं के आकर्षण के बीच पुरातत्व के भीतर द्वंद्व पर जोर देता है। परिच्छेद इस बात पर जोर देता है कि सच्ची पुरातात्विक का परिणाम अक्सर "संकीर्ण और अत्यधिक रूखा" होता है, लेकिन यह वास्तव में साक्ष्य और पद्धतिगत कठोरता का पालन है जो अनुशासन की अखंडता को रेखांकित करता है।
विकल्प a, b, और c ऐसे परिदृश्यों का सुझाव देते हैं जो एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पुरातत्व के चित्रण को कमजोर कर देंगे जहां सबसे आकर्षक अंतर्दृष्टि अक्सर पद्धतिगत परिश्रम और साक्ष्य के पालन की कीमत पर आती है। उनका तात्पर्य यह है कि आकर्षक कथाएँ, काल्पनिक सफलताएँ, या प्रकाशन मानकों का प्रभाव, परिच्छेद के तर्क के विपरीत, कठोरता और पठनीयता के बीच अनुशासन के अंतर्निहित तनाव को कम कर सकता है।

परिच्छेद-II

संज्ञानात्मक वृद्धि पर चर्चा में, न्यूरोएन्हांसमेंट/तंत्रिका संवर्द्धनीय प्रौद्योगिकियों के आसपास की नैतिक पहेली समकालीन जैवनैतिकता में सबसे आगे है। फार्मास्यूटिकल्स, मस्तिष्क उत्तेजना विधियों और जेनेटिक इंजीनियरिंग को शामिल करने वाली ये प्रौद्योगिकियां स्मृति, ध्यान और कार्यकारी नियंत्रण जैसे संज्ञानात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण सुधार का वादा करती हैं। हालाँकि, इस तरह के संवर्द्धन के आगमन ने मानव बुद्धि को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के नैतिक निहितार्थों पर एक उत्साही बहस छेड़ दी है। इस बहस के केंद्र में समानता और पहुंच से जुड़ी चिंता है। एक संज्ञानात्मक वृद्धि विभाजन की संभावना, जिसमें केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही इन प्रौद्योगिकियों को वहन कर सकते हैं, सामाजिक न्याय और मौजूदा असमानताओं के बढ़ने के बारे में गहरा सवाल उठाता है। इसके अलावा, मानव अनुभूति और समाज पर तंत्रिका संवर्द्धन के दीर्घकालिक प्रभाव काफी हद तक काल्पनिक बने हुए हैं, जो नैतिक विचारों को और अधिक जटिल बनाते हैं।
यह चर्चा प्रामाणिकता की धारणा और प्रयास के मूल्य से भी जूझती है। आलोचकों का तर्क है कि बढ़ी हुई क्षमताओं के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियाँ मानव प्रयास की प्रामाणिकता को कमजोर कर सकती हैं, प्रयास और संघर्ष के आंतरिक मूल्य पर परिणामों को महत्व दे सकती हैं। इसके विपरीत, प्रस्तावक तकनीकी प्रगति के माध्यम से मानव कल्याण में सुधार के लिए नैतिक अनिवार्यता की वकालत करते हुए, पीड़ा को कम करने और मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए न्यूरोएनहांसमेंट की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं।
चिकित्सीय हस्तक्षेपों और संवर्द्धन के बीच धुंधली रेखाओं के कारण यह नैतिक परिदृश्य और भी जटिल हो गया है। जबकि पहला घाटे को दूर करने और सामान्य कामकाज को बहाल करने का प्रयास करता है, दूसरे का लक्ष्य विशिष्ट या औसत क्षमताओं को पार करना है, जो कि मानव होने का क्या मतलब है की धारणा को चुनौती देता है।

WWW.PDFNOTES.CO

Q.50) निम्नलिखित में से कौन सी धारणा, यदि सत्य है, तो परिच्छेद में दिए गए तर्कों को कमजोर कर देगी?
a) विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के व्यक्तियों के लिए न्यूरोएनहांसमेंट प्रौद्योगिकियां आसानी से सुलभ और सस्ती हैं।
b) न्यूरोएनहांसमेंट प्रौद्योगिकियों का उपयोग मौजूदा सामाजिक असमानताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
c) न्यूरोएनहांसमेंट के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियाँ मानव प्रयास के अनुमानित मूल्य को कमजोर करती हैं।
d) न्यूरोएनहांसमेंट का उपयोग पीड़ा को कम करने और मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

Ans) a
Exp) विकल्प a सही उत्तर है।
यह परिच्छेद न्यूरोएन्हांसमेंट प्रौद्योगिकियों के नैतिक निहितार्थों के बारे में चिंताओं को रेखांकित करता है, जिसमें अंतर पहुंच और सामर्थ्य के कारण सामाजिक असमानताओं के बढ़ने का जोखिम भी शामिल है। यदि धारणा सत्य है, तो यह दर्शाता है कि न्यूरोएनहांसमेंट प्रौद्योगिकियां सामाजिक-आर्थिक स्तर पर सुलभ और सस्ती हैं, यह सीधे तौर पर अनुच्छेद में प्रस्तुत समानता और पहुंच पर चिंता का प्रतिकार करती है। यह धारणा सुझाव देगी कि संज्ञानात्मक वृद्धि विभाजन की संभावना कम हो गई है, जिससे यह तर्क कमजोर हो जाएगा कि न्यूरोएनहांसमेंट मौजूदा असमानताओं को गहरा कर सकता है।
विकल्प b, c, और d परिच्छेद में उठाए गए अन्य नैतिक चिंताओं को उजागर करते हैं लेकिन सीधे तौर पर दिए गए तर्कों को कमजोर नहीं करते हैं; इसके बजाय, वे संज्ञानात्मक वृद्धि प्रौद्योगिकियों के नैतिक मूल्यांकन से जुड़ी जटिलताओं और चुनौतियों को सुदृढ़ करते हैं।
Subject:) CSAT
Subtopic:) Reading Comprehension

WWW.PDFNOTES.CO